

22 June 2026: Top Current Affairs News GK (Hindi & English)

1] India is hosting a high-level two-day BRICS meeting starting June 22, 2026, in New Delhi. Which specific apex platform is convening under the chairmanship of NSA Ajit Doval?

भारत 22 जून 2026 से नई दिल्ली में दो दिवसीय उच्च स्तरीय ब्रिक्स बैठक की मेजबानी कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल की अध्यक्षता में किस विशिष्ट शीर्ष मंच का आयोजन किया जा रहा है?

A. BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting / ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक

B. BRICS National Security Advisers (NSA) Meeting / ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) की बैठक (BRICS NSA Meeting)

C. BRICS Environment Ministers Forum / ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का मंच

D. BRICS Counter-Terrorism Action Taskforce / ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी एक्शन टास्कफोर्स

Answer: B. BRICS National Security Advisers (NSA) Meeting / ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) की बैठक (BRICS NSA Meeting)

Explanation: India hosted the two-day BRICS National Security Advisers Meeting beginning June 22, 2026. Chaired by Indian NSA Ajit Doval, the high-level meeting brought together heads of delegations from BRICS member nations to exchange strategic views on "Non-traditional security challenges confronting the world today," focusing heavily on the evolving nature of new technologies and emerging security threats.

स्पष्टीकरण: भारत ने 22 जून 2026 से शुरू होने वाली दो दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSA) की बैठक की मेजबानी की। भारतीय एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने "दुनिया के सामने मौजूद गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां" विषय पर रणनीतिक विचार साझा किए, जिसमें नई तकनीकों और उभरते सुरक्षा खतरों पर मुख्य रूप से चर्चा की गई।

② The Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) around June 22, 2026, accelerated a massive ecological conservation draft. The government is preparing to notify Ecologically Sensitive Areas (ESAs) across which geographical feature covering at least three states?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 22 जून 2026 के आसपास एक बड़े पारिस्थितिक संरक्षण मसौदे को गति दी है। सरकार कम से कम तीन राज्यों में फैले किस भौगोलिक क्षेत्र को 'पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र' (ESA) अधिसूचित करने की तैयारी कर रही है?

- A. Indo-Gangetic Plains / भारत-गंगा के मैदान
- B. Western Ghats / पश्चिमी घाट (Western Ghats)
- C. Sundarbans Deltaic Region / सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र
- D. Eastern Himalayan Foothills / पूर्वी हिमालय की तलहटी

✓ **Answer: B. Western Ghats / पश्चिमी घाट (Western Ghats)**

Explanation: The Union Government has finalized intense preparations to officially notify Ecologically Sensitive Areas (ESAs) across the Western Ghats, spanning at least three major states. This long-pending regulatory step aims to strictly control commercial mining, highly polluting industrial setups, and unchecked urban expansion to protect the fragile, hyper-biodiverse mountain range.

स्पष्टीकरण: केंद्र सरकार ने कम से कम तीन प्रमुख राज्यों में फैले पश्चिमी घाट (Western Ghats) के क्षेत्रों को आधिकारिक तौर पर 'पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र' (ESA) अधिसूचित करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस लंबे समय से लंबित विनियामक कदम का उद्देश्य नाजुक और अत्यधिक जैव-विविधता वाले इस पर्वतीय क्षेत्र की रक्षा के लिए व्यावसायिक खनन, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और अनियंत्रित शहरी विस्तार को कड़ाई से नियंत्रित करना है।

③ In a major boost to clean energy self-reliance, which state-run thermal energy major has drawn expression of interest from global nuclear players for strategic Nuclear Technology (N-Tech) partnerships?

स्वच्छ ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, किस सरकारी थर्मल ऊर्जा दिग्गज कंपनी ने रणनीतिक परमाणु प्रौद्योगिकी (N-Tech) साझेदारी के लिए वैश्विक परमाणु दिग्गजों से रुचि पत्र (EoI) आकर्षित किया है?

- A. ONGC / ओएनजीसी
- B. NTPC Limited / एनटीपीसी लिमिटेड (NTPC)
- C. NHPC / एनएचपीसी
- D. GAIL India / गेल इंडिया

✓ **Answer: B. NTPC Limited / एनटीपीसी लिमिटेड (NTPC)**

Explanation: India's state-owned power giant NTPC Limited has successfully drawn interest from prominent global nuclear players for clean nuclear technology partnerships. As NTPC aggressively diversifies its traditional coal-heavy portfolio, these international alliances will target Small Modular Reactors (SMRs) and advanced nuclear tech implementation to meet India's green baseload requirements.

स्पष्टीकरण: भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली दिग्गज कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड (NTPC) ने स्वच्छ परमाणु ऊर्जा साझेदारी के लिए प्रमुख वैश्विक परमाणु दिग्गजों से रुचि आकर्षित की है। चूंकि एनटीपीसी अपने पारंपरिक कोयला-आधारित पोर्टफोलियो में बदलाव कर रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन भारत की हरित ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) और उन्नत परमाणु तकनीक के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

4) The Madras High Court on June 22, 2026, took up a critical suo motu Public Interest Litigation (PIL) to monitor the implementation of apex court guidelines. What public safety concern does this PIL directly target?

मद्रास उच्च न्यायालय ने 22 जून 2026 को सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका (PIL) पर स्वतः संज्ञान (suo motu) लिया है। यह जनहित याचिका सीधे तौर पर किस सार्वजनिक सुरक्षा चिंता को लक्षित करती है?

- A. Overcrowded Local Electronic Trains / खचाखच भरी लोकल इलेक्ट्रिक ट्रेनें

B. Protection of citizens from stray dog attacks / आवारा कुत्तों के हमलों से नागरिकों की सुरक्षा (Stray Dog Management)

C. Illegal Groundwater Extraction by private tankers / निजी टैंकरों द्वारा अवैध भूजल दोहन

D. Plastic Waste Accumulation in Coastal Zones / तटीय क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे का जमाव

✓ **Answer: B. Protection of citizens from stray dog attacks / आवारा कुत्तों के हमलों से नागरिकों की सुरक्षा (Stray Dog Management)**

Explanation: The Madras High Court took up a suo motu PIL to ensure strict and uniform implementation of recent Supreme Court orders aimed at protecting people from stray dog attacks across Tamil Nadu and Puducherry. The bench impleaded Chief Secretaries and the Animal Husbandry department to report on vaccination, sterilisation, and safety enforcement metrics.

स्पष्टीकरण: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में आवारा कुत्तों के हमलों से लोगों को बचाने के उद्देश्य से हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को कड़ाई से लागू करने के लिए एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका (PIL) ली है। अदालत ने मुख्य सचिवों और पशुपालन विभाग को पक्षकार बनाते हुए टीकाकरण, नसबंदी और सुरक्षा उपायों पर रिपोर्ट मांगी है।

5) The National Skill Development Corporation (NSDC) has launched a widespread investigative enforcement crackdown across India. Officials are serving accountability notices for severe operational lapses under which flagship central scheme?

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) ने भारत भर में एक व्यापक खोजी प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की है। अधिकारी किस प्रमुख केंद्रीय योजना के तहत गंभीर परिचालन कमियों के लिए जवाबदेही नोटिस जारी कर रहे हैं?

A. Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) / प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

B. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) / प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

C. PM Svanidhi Scheme / पीएम स्वनिधि योजना

D. Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana / दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

Answer: B. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) / प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

Explanation: The National Skill Development Corporation (NSDC) has intensified its systemic cleanup by serving legal and operational notices to several current and former staffers. The enforcement actions are tied to audited financial and quality "lapses" discovered within training execution modules of the government's flagship skill-building program, the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY).

स्पष्टीकरण: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) ने कई वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों को कानूनी और परिचालन नोटिस जारी करके अपनी प्रणालीगत सफाई तेज कर दी है। यह कार्रवाई सरकार के प्रमुख कौशल विकास कार्यक्रम, 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' (PMKVY) के प्रशिक्षण मॉड्यूल में पाई गई वित्तीय और गुणवत्ता संबंधी कमियों (lapses) से जुड़ी है।

6 High-level diplomatic and ministerial-level discussions scheduled for late June 2026 are focusing heavily on restructuring supply lines away from the volatile Strait of Hormuz. For which critical domestic energy strategy does India rely heavily on the Hormuz maritime transit corridor?

जून 2026 के अंत में होने वाली उच्च स्तरीय राजनयिक और मंत्री-स्तरीय चर्चाएं अस्थिर 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) से दूर अपनी आपूर्ति लाइनों को पुनर्गठित करने पर केंद्रित हैं। भारत अपनी किस महत्वपूर्ण घरेलू ऊर्जा रणनीति के लिए मुख्य रूप से हॉर्मुज समुद्री पारगमन गलियारे पर निर्भर है?

A. National Green Hydrogen Mission / राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

B. Liquefied Petroleum Gas (LPG) Imports / तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) आयात (LPG Strategy)

C. Domestic Shale Gas Hydrofracking / घरेलू शेल गैस हाइड्रोफ्रैकिंग

D. Strategic Offshore Wind Grid / रणनीतिक अपतटीय पवन ग्रिड

Answer: B. Liquefied Petroleum Gas (LPG) Imports / तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) आयात (LPG Strategy)

Explanation: The recent geopolitical volatility around Iran and the Western powers has highlighted India's intense strategic vulnerability in its Liquefied Petroleum Gas (LPG) supply chain. India relies massively on imports passing through the narrow Strait of Hormuz, handled by a limited Indian-flagged fleet with minimal long-term cavern storage, forcing policy experts to rapidly draft alternative land-sea energy corridors.

स्पष्टीकरण: ईरान और पश्चिमी ताकतों के बीच हालिया भू-राजनीतिक उथल-पुथल ने भारत की तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) आपूर्ति श्रृंखला में भारी रणनीतिक कमजोरी को उजागर किया है। भारत संकीर्ण हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसके लिए भारत के पास सीमित जहाजी बेड़ा और बहुत कम दीर्घकालिक भंडारण क्षमता है। यही कारण है कि नीति विशेषज्ञ अब वैकल्पिक ऊर्जा गलियारों का मसौदा तैयार कर रहे हैं।

7] The Lok Sabha Standing Committee on Finance, in its latest June 2026 official bulletin, selected which urgent subject for comprehensive examination during the fiscal year 2025-26 amid global tariff uncertainties?

वित्त पर लोकसभा की स्थायी समिति ने अपने नवीनतम जून 2026 के आधिकारिक बुलेटिन में, वैश्विक टैरिफ अनिश्चितताओं के बीच वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विस्तृत जांच के लिए किस तत्काल विषय को चुना है?

- A. Decarbonization of Commercial Real Estate / वाणिज्यिक रीयल एस्टेट का वि-कार्बनिकरण
- B. Evolving Economic Conditions in the Country / देश में उभरती आर्थिक स्थितियां (Evolving Economic Conditions)
- C. Sovereign Cryptographic Asset Regulations / संप्रभु क्रिप्टोग्राफिक संपत्ति नियमन
- D. Digitization of Rural Microfinance Institutions / ग्रामीण सूक्ष्म वित्त संस्थानों का डिजिटलीकरण

Answer: B. Evolving Economic Conditions in the Country / देश में उभरती आर्थिक स्थितियां (Evolving Economic Conditions)

Explanation: Prompted by shifting global tariff policies, prolonged regional conflicts, and disrupted maritime shipping routes, the parliamentary Standing Committee on Finance has officially added "Evolving Economic Conditions in

the Country" as a core subject for meticulous investigation during the 2025-26 cycle to prepare risk-mitigation buffers for domestic industries.

स्पष्टीकरण: बदलते वैश्विक टैरिफ नियमों, लंबे समय से चल रहे क्षेत्रीय संघर्षों और समुद्री व्यापार मार्गों में व्यवधानों को देखते हुए, संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2025-26 के लिए "देश में उभरती आर्थिक स्थितियां" (Evolving Economic Conditions in the Country) को एक अतिरिक्त विषय के रूप में चुना है, ताकि घरेलू उद्योगों के लिए जोखिमों को कम किया जा सके।

8] The Special Investigation Team (SIT) operating out of Uttar Pradesh issued instructions to temple trust functionaries not to leave Ayodhya. This executive directive is linked to documented discrepancies in which specific administrative domain?

उत्तर प्रदेश में सक्रिय विशेष जांच दल (SIT) ने मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को अयोध्या न छोड़ने के निर्देश जारी किए हैं। यह कार्यकारी निर्देश किस विशिष्ट प्रशासनिक क्षेत्र में पाई गई विसंगतियों से जुड़ा है?

- A. Encroachment of Forest Buffer Zones / वन बफर जोन का अतिक्रमण
- B. Embezzlement and documentation discrepancies of sacred offerings / पवित्र चढ़ावे के गबन और दस्तावेज़ीकरण में विसंगतियां (Discrepancies in Offerings Documentation)
- C. Heritage structural security violations / विरासत संरचनात्मक सुरक्षा उल्लंघन
- D. Retail Vendor License Mismanagement / खुदरा विक्रेता लाइसेंस कुप्रबंधन

✓ **Answer: B. Embezzlement and documentation discrepancies of sacred offerings / पवित्र चढ़ावे के गबन और दस्तावेज़ीकरण में विसंगतियां (Discrepancies in Offerings Documentation)**

Explanation: The three-member SIT probing allegations of irregularities and fund embezzlement at the Ram Temple in Ayodhya directed key functionaries to stay stationed in the city. The order was issued after investigators unhedged major documentation discrepancies and accounting mismatches concerning valuable offerings, including gold, silver, and precious gemstones.

स्पष्टीकरण: अयोध्या में राम मंदिर के कोष और धन के कथित गबन की जांच कर रही तीन सदस्यीय एसआईटी (SIT) ने प्रमुख पदाधिकारियों को शहर में ही रहने के निर्देश दिए हैं।

जांचकर्ताओं को सोने, चांदी और कीमती रत्नों सहित मूल्यवान चढ़ावे के दस्तावेज़ीकरण और लेखांकन (accounting) में बड़ी विसंगतियां मिलने के बाद यह आदेश जारी किया गया है।

9) The South-West Monsoon's progress encountered a notable atmospheric stalling phase over southern Maharashtra. According to the comprehensive IMD data released up to late June 2026, what percentage of cumulative rainfall deficit did India face nationwide between June 4 and June 18?

दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति में दक्षिणी महाराष्ट्र के ऊपर एक उल्लेखनीय ठहराव देखा गया। जून 2026 के मध्य तक जारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के व्यापक आंकड़ों के अनुसार, 4 जून से 18 जून के बीच भारत को देशव्यापी स्तर पर कितने प्रतिशत संचयी वर्षा घाटे (rainfall deficit) का सामना करना पड़ा?

- A. 15%
- B. 28%
- C. 41% (41% Deficit)
- D. 53%

✓ **Answer: C. 41% (41% Deficit)**

Explanation: Official data tracking released by the India Meteorological Department (IMD) revealed that due to a prolonged stalling phase of the southwest monsoon over southern Maharashtra, India faced a heavy nationwide rainfall deficit of 41% between June 4 and June 18. Despite intense localized flooding caused by different weather systems in North Bengal and Assam, the central and western crop belts remained dry.

स्पष्टीकरण: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि दक्षिणी महाराष्ट्र के ऊपर दक्षिण-पश्चिम मानसून के लंबे समय तक थमे रहने के कारण, 4 जून से 18 जून के बीच भारत को देशव्यापी स्तर पर 41% के भारी वर्षा घाटे का सामना करना पड़ा। हालांकि उत्तर बंगाल और असम में अलग प्रणालियों के कारण भारी बारिश हुई, लेकिन मध्य और पश्चिमी कृषि क्षेत्र सूखे रहे।

10) The apex command of the Indian Navy on June 22, 2026, fast-tracked active logistics monitoring after an international commercial vessel, MV Sky

Light, continued to remain stranded near Indian shores. MV Sky Light was heavily compromised earlier due to which specific global security hazard?

भारतीय नौसेना के शीर्ष कमान ने 22 जून 2026 को एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक जहाज 'एमवी स्काई लाइट' (MV Sky Light) के भारतीय तटों के पास फंसे रहने के बाद सक्रिय लॉजिस्टिक्स निगरानी तेज कर दी है। एमवी स्काई लाइट पहले किस विशिष्ट वैश्विक सुरक्षा खतरे के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था?

- A. Cyber-Hijacking of its automated GPS grid / इसके स्वचालित जीपीएस ग्रिड की साइबर-हाइजैकिंग
- B. High-Seas Missile Strike / गहरे समुद्र में मिसाइल हमला (Missile Strike)
- C. Deepwater Marine Mine Collison / गहरे पानी में समुद्री माइन से टक्कर
- D. Eco-Toxic Fuel Core Leak / इको-टॉक्सिक ईंधन कोर रिसाव

Answer: B. High-Seas Missile Strike / गहरे समुद्र में मिसाइल हमला (Missile Strike)

Explanation: The commercial oil and cargo tanker MV Sky Light has been anchored under distress near Mumbai for three months following a devastating missile strike on the high seas amid ongoing maritime conflict zones. Indian maritime authorities and the Navy are directly overseeing the welfare and documentation clearance of the stranded sailors who lost their legal identification and job papers in the onboard missile fire.

स्पष्टीकरण: चल रहे समुद्री संघर्ष क्षेत्रों के बीच गहरे समुद्र में हुए एक विनाशकारी मिसाइल हमले के बाद वाणिज्यिक टैंकर एमवी स्काई लाइट (MV Sky Light) पिछले तीन महीनों से मुंबई के पास संकट में खड़ा है। भारतीय समुद्री अधिकारी और नौसेना उन फंसे हुए नाविकों के कल्याण और दस्तावेज़ीकरण की सीधे देखरेख कर रहे हैं, जिन्होंने जहाज पर मिसाइल से लगी आग में अपने कानूनी पहचान पत्र और नौकरी के कागजात खो दिए थे।